



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012024-251148  
CG-DL-E-04012024-251148

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2024/पौष 14, 1945

No. 14]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 17(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्: ---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2019 में, अनुसूची में, सहायक खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, -

(क) स्तंभ (9) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

"दो वर्ष।

टिप्पण: सीधी भर्ती वाले लोगों को परिवीक्षा पूरी करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।";

(ख) स्तंभ (11) में, -

(i) उप-शीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-शीर्षक "प्रोन्नति" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात तथा टिप्पण 1 से पूर्व, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्: -

**"टिप्पण 1:** खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (रु. 44900-142400) में स्तर 7 में खनिज अधिकारी (आसूचना) के फीडर पद के संबंध में पात्रता सेवा तीन वर्ष जारी रहेगी।"

(iii) "टिप्पण 1" को "टिप्पण 2" के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा।

[फा. सं. 22/1/2023-खानIII]

संजय लोहिया, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 789(अ) तारीख 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF MINES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2024

**G.S.R. 17(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Group 'A' and 'B' Posts Recruitment Rules, 2019, namely:—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Group 'A' and 'B' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Group 'A' and 'B' Posts Recruitment Rules, 2019, in the Schedule, against serial number 5 relating to the post of Assistant Mineral Economist (Intelligence), -

(a) in column (9), for the entries, the following shall be substituted, namely: -

"Two years.

**Note:** Direct recruits shall be required to successfully complete a mandatory induction training of at least two weeks duration, as prescribed by the competent authority, for completion of probation.";

(b) in column (11), -

(i) under the sub-heading "Promotion", for the words "three years", the words "five years" shall be substituted;

(ii) after sub-heading "Promotion" and the entries relating thereto and before Note 1, the following Note shall be inserted, namely: -

**"Note 1:** The eligibility service shall continue to be three years in respect of incumbents holding the feeder post of Mineral Officer (Intelligence) in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) on regular basis on the date of notification of the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Group 'A' and 'B' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2023."

(iii) "Note 1" shall be renumbered as "Note 2".

[F. No. 22/1/2023-M.III]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (i), *vide* notification number G.S.R 789(E), dated the 15<sup>th</sup> October, 2019.